

प्रदेश में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिये दूसरे समग्र पुनर्वास केंद्र (सीआरसी) की सेवाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

8 अप्रैल, 2023 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के छतरपुर के महलानगेट स्थिति पुराने तहसील भवन में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिये समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) की सेवाओं का उद्घाटन किया।

प्रमुख बंदि

- कार्यक्रम में डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह सीआरसी नवाचार एवं शक्ति का एक केंद्र बनेगा और दिव्यांगजनों के लिये बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन को संभव बनाने हेतु जनशक्ति एवं अनुसंधान संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा ताकि दिव्यांगजन समाज के विकास में योगदान कर सकें।
- उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को एक छत के नीचे लाकर और संबद्ध सेवाओं की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित कर छतरपुर और उसके आसपास के इलाकों में विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के समक्ष समाज में पेश आने वाली कुछ सबसे कठिन चुनौतियों से निपटने की भी योजना है।
- समारोह में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह नया सीआरसी दिव्यांगजनों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करेगा और मध्य प्रदेश राज्य में मानव संसाधन विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छतरपुर ज़िले में प्रदान की गई दो हेक्टेयर भूमि पर सीआरसी-छतरपुर के भवन का निर्माण भी शीघ्र शुरू किया जाएगा।
- यह नया सीआरसी दिव्यांगजनों के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के अलावा दिव्यांगता की 21 श्रेणियों के लिये पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करेगा।
- दिव्यांगजनों के लिये सहायता एवं उपकरण और यूनियर्सल आइडेंटिटी (यूडीआईडी) कार्ड वितरित करने के लिये शिविर आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। यह कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। सुगम्य भारत अभियान की दशा में नई पहल की जाएगी। यह अभियान दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने हेतु देश भर में जारी है।
- सीआरसी-छतरपुर द्वारा दिव्यांग छात्रों को बना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रखने के लिये वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।
- गौरतलब है कि भोपाल, अहमदाबाद और नागपुर स्थिति सीआरसी के अलावा सीआरसी-छतरपुर का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत मुंबई स्थिति अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्प्रीच एंड हयिरिंग डिसएबिलिटीज (दिव्यांगजन) एवाईजेनआईएसएचडी (डी) के पास है।